

Roll. No.

Question Booklet Number

O.M.R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

M.A. (SEM.-IV) (NEP) (SUPPLE.) EXAMINATION, 2024-25

POLITICAL SCIENCE

(Public Policy & Administration in India)

Paper Code

A	0	6	1	0	0	3	T
---	---	---	---	---	---	---	---

**Question Booklet
Series**

A

Time : 1 : 30 Hours

Max. Marks : 75

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 100 questions. Examinee is required to answer 75 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.
4. Four alternative answers are mentioned for each question as - A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the correct / answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

(Remaining instructions on last page)

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को 75 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, उसे तुरन्त बदल लें।
4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर- A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से सही उत्तर छानना है। उत्तर को OMR उत्तर-पत्रक में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

1. Public policy can be defined as:
 - (A) Private business strategy
 - (B) A course of action adopted by the government to solve public problems
 - (C) Personal decisions of citizens
 - (D) International treaties only
2. Which scholar defined public policy as “whatever government chooses to do or not to do”?
 - (A) Harold Lasswell
 - (B) Simon Smith
 - (C) Richard Dye
 - (D) Woodrow Wilson
3. Public policy is normative in nature because:
 - (A) It prescribes what ought to be done
 - (B) It is voluntary for citizens
 - (C) It is purely descriptive
 - (D) It has no objectives
4. The scope of public policy includes:
 - (A) Economic policies
 - (B) Social policies
 - (C) Foreign policies
 - (D) All of the above
5. Public policy is important because it:
 - (A) Guides government action
 - (B) Promotes social welfare
 - (C) Resolves conflicts in society
 - (D) All of the above

1. सार्वजनिक नीति को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है :
 - (A) निजी व्यापार रणनीति
 - (B) जनता की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कार्रवाई
 - (C) नागरिकों के व्यक्तिगत निर्णय
 - (D) केवल अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
2. किस विद्वान ने सार्वजनिक नीति को “जो कुछ भी सरकार करती है या नहीं करती है” के रूप में परिभाषित किया ?
 - (A) हैरोल्ड लैसवेल
 - (B) साइमन स्मिथ
 - (C) रिचर्ड डाय
 - (D) वुडरो विल्सन
3. सार्वजनिक नीति प्रकृति में मानकात्मक (Normative) है क्योंकि :
 - (A) यह बताती है कि क्या किया जाना चाहिए
 - (B) यह नागरिकों के लिए स्वैच्छिक है
 - (C) यह केवल वर्णनात्मक है
 - (D) इसका कोई उद्देश्य नहीं है
4. सार्वजनिक नीति के दायरे में शामिल है :
 - (A) आर्थिक नीतियाँ
 - (B) सामाजिक नीतियाँ
 - (C) विदेश नीतियाँ
 - (D) उपरोक्त सभी
5. सार्वजनिक नीति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह :
 - (A) सरकारी कार्रवाई को मार्गदर्शित करती है
 - (B) सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देती है
 - (C) समाज में संघर्षों को हल करती है
 - (D) उपरोक्त सभी

- | | |
|---|---|
| <p>6. Public policy helps in:</p> <p>(A) Nation-building</p> <p>(B) Maintaining law and order</p> <p>(C) Promoting economic growth</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>6. सार्वजनिक नीति में मदद करती है :</p> <p>(A) राष्ट्र निर्माण</p> <p>(B) कानून और व्यवस्था बनाए रखने</p> <p>(C) आर्थिक विकास को बढ़ावा देने</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |
| <p>7. The Rational-Comprehensive approach in policy-making emphasizes:</p> <p>(A) Quick decision-making without data</p> <p>(B) Systematic analysis of all alternatives before decision</p> <p>(C) Decisions based on tradition only</p> <p>(D) Ignoring costs and benefits</p> | <p>7. नीति निर्माण में तर्कसंगत-सर्वसमावेशी दृष्टिकोण क्या महत्व देता है ?</p> <p>(A) बिना आँकड़ों के त्वरित निर्णय लेना</p> <p>(B) निर्णय से पहले सभी विकल्पों का व्यवस्थित विश्लेषण करना</p> <p>(C) केवल परंपरा के आधार पर निर्णय लेना</p> <p>(D) लागत-लाभ की अनदेखी करना</p> |
| <p>8. The Incremental approach was proposed by:</p> <p>(A) Harold Lasswell</p> <p>(B) Charles Lindblom</p> <p>(C) Richard Dye</p> <p>(D) Woodrow Wilson</p> | <p>8. क्रमिक दृष्टिकोण का प्रस्ताव किसने रखा था ?</p> <p>(A) हैरोल्ड लैसवेल</p> <p>(B) चार्ल्स लिंडब्लॉम</p> <p>(C) रिचर्ड डई</p> <p>(D) वुड्रो विल्सन</p> |
| <p>9. Incrementalism focuses on:</p> <p>(A) Major revolutionary changes</p> <p>(B) Small, gradual adjustments to existing policies</p> <p>(C) Ignoring past policies</p> <p>(D) Unilateral decisions</p> | <p>9. क्रमिकता का ध्यान मुख्यतः किस पर होता है?</p> <p>(A) बड़े क्रांतिकारी परिवर्तन</p> <p>(B) मौजूदा नीतियों में छोटे-छोटे क्रमिक समायोजन</p> <p>(C) पिछली नीतियों की अनदेखी</p> <p>(D) एकतरफा निर्णय लेना</p> |
| <p>10. The Mixed-Scanning approach combines:</p> <p>(A) Comprehensive analysis and incremental adjustments</p> <p>(B) Only cost-benefit analysis</p> <p>(C) Political lobbying</p> <p>(D) Random decision-making</p> | <p>10. मिश्रित-निरीक्षण (Mixed-Scanning) दृष्टिकोण क्या मिलाता है ?</p> <p>(A) व्यापक विश्लेषण और क्रमिक समायोजन दोनों को मिलाकर</p> <p>(B) केवल लागत-लाभ विश्लेषण को</p> <p>(C) केवल राजनीतिक लॉबींग को</p> <p>(D) यादृच्छिक निर्णयों को</p> |

- | | |
|--|--|
| <p>11. Which scholar proposed the Mixed-Scanning approach?</p> <p>(A) Charles Lindblom</p> <p>(B) Amitai Etzioni</p> <p>(C) Richard Dye</p> <p>(D) Harold Lasswell</p> | <p>11. मिश्रित-निरीक्षण दृष्टिकोण किस विद्वान ने प्रस्तावित किया था ?</p> <p>(A) चार्ल्स लिंडब्लॉम</p> <p>(B) अमिताई एज़िओनी</p> <p>(C) रिचर्ड डई</p> <p>(D) हैरोल्ड लैसवेल</p> |
| <p>12. Incrementalism is also known as:</p> <p>(A) “Muddling through”</p> <p>(B) “Top-down planning”</p> <p>(C) “Grand design”</p> <p>(D) “Rational planning”</p> | <p>12. क्रमिक दृष्टिकोण को सामान्यतः किस रूप में भी जाना जाता है ?</p> <p>(A) अनियोजित तरीके से काम चलाना (अव्यवस्थित रूप से काम चलाना)</p> <p>(B) ऊपर-से-नीचे योजना</p> <p>(C) भव्य डिज़ाइन</p> <p>(D) तर्कसंगत योजना</p> |
| <p>13. Policy-making is considered a continuous process because:</p> <p>(A) Policies are evaluated, adjusted, and implemented continuously</p> <p>(B) Once made, policies never change</p> <p>(C) Policies only occur once every election</p> <p>(D) Policies are purely theoretical</p> | <p>13. नीति-निर्माण को एक निरंतर प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि :</p> <p>(A) नीतियों का मूल्यांकन, समायोजन और कार्यान्वयन लगातार होता रहता है</p> <p>(B) एक बार बनने के बाद नीतियाँ कभी नहीं बदलती</p> <p>(C) नीतियाँ केवल चुनावों के समय बनती हैं</p> <p>(D) नीतियाँ केवल सैद्धांतिक होती हैं</p> |
| <p>14. The choice of policy-making approach depends on:</p> <p>(A) Complexity of problem</p> <p>(B) Availability of resources</p> <p>(C) Political context</p> <p>(D) All of the above</p> | <p>14. नीति-निर्माण दृष्टिकोण का चयन किस पर निर्भर करता है ?</p> <p>(A) समस्या की जटिलता पर</p> <p>(B) संसाधनों की उपलब्धता पर</p> <p>(C) राजनीतिक संदर्भ पर</p> <p>(D) उपरोक्त सभी</p> |

15. Which institution in India is primarily responsible for making laws that guide public policy?
- (A) Judiciary
(B) Legislature (Parliament/State Assemblies)
(C) Executive
(D) Election Commission
16. The role of the executive in policy-making mainly involves:
- (A) Law interpretation
(B) Law implementation and drafting policies
(C) Law adjudication
(D) Reviewing constitutional amendments
17. Which institution plays the role of interpreting and reviewing the constitutionality of policies?
- (A) Legislature
(B) Executive
(C) Judiciary
(D) Planning Commission
18. In India, which body replaced the Planning Commission in 2015 as a key policy making institution?
- (A) Finance Commission
(B) NITI Aayog
(C) CAG
(D) Election Commission
15. भारत में सार्वजनिक नीति से संबंधित कानून बनाने की मुख्य जिम्मेदारी किस संस्था की है ?
- (A) न्यायपालिका
(B) विधायिका (संसद/विधानसभाएँ)
(C) कार्यपालिका
(D) निर्वाचन आयोग
16. कार्यपालिका की भूमिका नीति-निर्माण में मुख्यतः क्या होती है ?
- (A) कानून की व्याख्या करना
(B) कानूनों को लागू करना और नीतियाँ बनाना
(C) कानून का निर्णय देना
(D) संवैधानिक संशोधनों की समीक्षा करना
17. कौन-सी संस्था नीतियों की व्याख्या करने और उनकी संवैधानिकता की समीक्षा करने का काम करती है ?
- (A) विधायिका
(B) कार्यपालिका
(C) न्यायपालिका
(D) योजना आयोग
18. भारत में 2015 में नीति-निर्माण की प्रमुख संस्था के रूप में योजना आयोग की जगह किसने ली ?
- (A) वित्त आयोग
(B) नीति आयोग
(C) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
(D) निर्वाचन आयोग

- | | |
|--|--|
| <p>19. The bureaucracy's role in policy-making is primarily:</p> <p>(A) Enacting laws</p> <p>(B) Advising, drafting, and executing policies</p> <p>(C) Electing representatives</p> <p>(D) Constitutional review</p> <p>20. Which institution ensures financial accountability of policies in India?</p> <p>(A) Finance Commission</p> <p>(B) CAG (Comptroller and Auditor General)</p> <p>(C) NITI Aayog</p> <p>(D) President</p> <p>21. Political parties influence policy-making mainly through:</p> <p>(A) Judicial review</p> <p>(B) Electoral promises, manifestos, and legislative debates</p> <p>(C) Budget auditing</p> <p>(D) Administrative rules</p> <p>22. The role of interest groups and pressure groups in policy-making is to:</p> <p>(A) Implement laws</p> <p>(B) Influence decision-makers through lobbying and advocacy</p> <p>(C) Conduct elections</p> <p>(D) Interpret constitutional provisions</p> | <p>19. नीति-निर्माण में नौकरशाही की मुख्य भूमिका क्या है ?</p> <p>(A) कानून बनाना</p> <p>(B) नीतियों का मसौदा तैयार करना, सलाह देना और उन्हें लागू करना</p> <p>(C) प्रतिनिधियों का चुनाव करना</p> <p>(D) संवैधानिक समीक्षा करना</p> <p>20. भारत में नीतियों की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने वाली संस्था कौन-सी है ?</p> <p>(A) वित्त आयोग</p> <p>(B) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)</p> <p>(C) नीति आयोग</p> <p>(D) राष्ट्रपति</p> <p>21. राजनीतिक दल नीति-निर्माण को मुख्यतः कैसे प्रभावित करते हैं ?</p> <p>(A) न्यायिक समीक्षा से</p> <p>(B) चुनावी वादों, घोषणापत्रों और विधायी बहसों के माध्यम से</p> <p>(C) बजट ऑडिटिंग से</p> <p>(D) प्रशासनिक नियमों से</p> <p>22. नीति-निर्माण में हित समूहों और दबाव समूहों की भूमिका क्या है ?</p> <p>(A) कानूनों को लागू करना</p> <p>(B) निर्णयकर्ताओं को लॉबींग और जनसंपर्क के माध्यम से प्रभावित करना</p> <p>(C) चुनाव कराना</p> <p>(D) संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करना</p> |
|--|--|

23. Which parliamentary tool is often used to influence or shape government policy?
- (A) Judicial writs
(B) Question Hour and Parliamentary Committees
(C) Ordinances by the President
(D) Executive orders
24. Media as an institution of policy-making is best described as:
- (A) A decision-making body
(B) A pressure institution shaping public opinion and agenda
(C) A judicial authority
(D) A financial regulator
25. The top-down approach in policy implementation assumes that:
- (A) Local actors have maximum autonomy
(B) Policy decisions are controlled by higher authorities and passed down for execution
(C) Citizens design the policy
(D) Only judiciary is responsible for implementation
26. Which level of government is most dominant in the top-down model?
- (A) Local level
(B) State level
(C) Central or higher authority
(D) Community organizations
23. संसद का कौन-सा उपकरण अक्सर सरकारी नीतियों को प्रभावित या आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है ?
- (A) न्यायिक रिट
(B) प्रश्नकाल और संसदीय समितियाँ
(C) राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश
(D) कार्यपालिका आदेश
24. नीति-निर्माण में मीडिया को किस रूप में सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है ?
- (A) एक निर्णय लेने वाली संस्था
(B) एक दबाव संस्था जो जनमत और एजेंडा को आकार देती है
(C) एक न्यायिक प्राधिकरण
(D) एक वित्तीय नियंत्रक
25. शीर्ष-से-नीचे (Top-Down) दृष्टिकोण यह मानता है कि :
- (A) स्थानीय अभिनेताओं के पास अधिकतम स्वायत्तता होती है
(B) नीतिगत निर्णय उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं और कार्यान्वयन के लिए नीचे भेजे जाते हैं
(C) नागरिक नीति तैयार करते हैं
(D) केवल न्यायपालिका कार्यान्वयन की जिम्मेदार होती है
26. शीर्ष-से-नीचे मॉडल में सरकार का कौन-सा स्तर सबसे प्रभावशाली होता है ?
- (A) स्थानीय स्तर
(B) राज्य स्तर
(C) केंद्रीय या उच्च प्राधिकरण
(D) सामुदायिक संगठन

27. The top-down approach emphasizes:
- Participation of grassroots actors
 - Strict adherence to official goals and directives
 - Flexibility in local adaptations
 - Citizen feedback in policy redesign
28. A major criticism of the top-down approach is:
- It ignores central authority
 - It fails to consider local conditions and actors' discretion
 - It allows too much flexibility
 - It is too participatory
29. A key advantage of the top-down approach is:
- It provides uniformity and clear authority in implementation
 - It maximizes local flexibility
 - It reduces bureaucratic control
 - It empowers marginalized groups
30. The bottom-up approach to policy implementation emphasizes:
- Centralized authority and control
 - Local-level actors and street-level bureaucrats
 - Judicial interpretation only
 - Media's role in shaping opinion
27. शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण बल देता है :
- जमीनी स्तर के अभिनेताओं की भागीदारी पर
 - आधिकारिक उद्देश्यों और निर्देशों के सख्त पालन पर
 - स्थानीय अनुकूलनों में लचीलापन पर
 - नागरिक प्रतिक्रिया को नीति पुनः डिज़ाइन में शामिल करने पर
28. शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण की एक प्रमुख आलोचना है :
- यह केंद्रीय अधिकार की अनदेखी करता है
 - यह स्थानीय परिस्थितियों और अभिनेताओं के विवेक की अनदेखी करता है
 - यह बहुत अधिक लचीलापन देता है
 - यह अत्यधिक सहभागितापूर्ण है
29. शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण का एक प्रमुख लाभ क्या है ?
- यह कार्यान्वयन में एकरूपता और स्पष्ट अधिकार प्रदान करता है
 - यह स्थानीय लचीलापन को अधिकतम करता है
 - यह नौकरशाही नियंत्रण को कम करता है
 - यह हाशिए के समूहों को सशक्त करता है
30. नीति-कार्यान्वयन में नीचे-से-ऊपर (Bottom-Up) दृष्टिकोण किस पर बल देता है ?
- केंद्रीकृत अधिकार और नियंत्रण पर
 - स्थानीय स्तर के अभिनेताओं और सड़क-स्तरीय नौकरशाहों पर
 - केवल न्यायिक व्याख्या पर
 - जनमत बनाने में मीडिया की भूमिका पर

31. Which scholar is associated with the concept of street-level bureaucrats?
- (A) Michael Lipsky
(B) Aaron Wildavsky
(C) Charles Lindblom
(D) Amitai Etzioni
32. The bottom-up approach assumes that successful implementation depends on:
- (A) Strict central directives
(B) Flexibility and discretion of local implementers
(C) Presidential orders
(D) Parliamentary supremacy
33. A major advantage of the bottom-up approach is:
- (A) Policies fit better with local conditions and needs
(B) Policies remain uniform everywhere
(C) Citizens have no role
(D) It reduces the role of local bureaucracy
34. The “implementation game” refers to:
- (A) Legal battles in courts
(B) Strategic bargaining, negotiation, and adaptation among implementers
(C) A fixed top-down procedure
(D) Media competition during elections
31. सड़क-स्तरीय नौकरशाहों (street-level bureaucrats) की संकल्पना किस विद्वान ने दी ?
- (A) माइकल लिप्स्की
(B) आरोन वाइल्डव्स्की
(C) चार्ल्स लिंडब्लॉम
(D) अमिताई एत्ज़िओनी
32. नीचे-से-ऊपर दृष्टिकोण मानता है कि सफल कार्यान्वयन किस पर निर्भर करता है ?
- (A) सख्त केंद्रीय आदेशों पर
(B) स्थानीय कार्यान्वयनकर्ताओं के लचीलापन और विवेक पर
(C) राष्ट्रपति के आदेशों पर
(D) संसद की सर्वोच्चता पर
33. नीचे-से-ऊपर दृष्टिकोण का एक प्रमुख लाभ क्या है?
- (A) नीतियाँ स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप बेहतर होती हैं
(B) नीतियाँ हर जगह समान रहती हैं
(C) नागरिकों की कोई भूमिका नहीं होती
(D) यह स्थानीय नौकरशाही की भूमिका कम कर देता है
34. “Implementation game” का अर्थ है :
- (A) न्यायालयों में कानूनी लड़ाइयाँ
(B) कार्यान्वयनकर्ताओं के बीच रणनीतिक सौदेबाजी, वार्ता और अनुकूलन
(C) एक निश्चित शीर्ष-से-नीचे प्रक्रिया
(D) चुनावों के दौरान मीडिया प्रतिस्पर्धा

35. According to the implementation game perspective, policy success depends on:
- Only political speeches
 - Interaction and compromises between various stakeholders
 - Rigid application of rules
 - Elimination of local discretion
36. A key criticism of the bottom-up approach is:
- It ignores central planning and may cause inconsistency
 - It gives too much uniformity
 - It denies local needs
 - It depends only on courts
37. Street-level bureaucrats mainly include:
- Members of Parliament
 - Local officials like teachers, police officers, welfare officers
 - High court judges
 - Cabinet ministers
38. According to Lipsky, street-level bureaucrats act as:
- Purely rule-followers
 - Policy-makers in practice
 - Only administrators of orders
 - Neutral record-keepers
35. “Implementation game” दृष्टिकोण के अनुसार नीति की सफलता किस पर निर्भर करती है ?
- केवल राजनीतिक भाषणों पर
 - विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और समझौतों पर
 - नियमों के कठोर अनुप्रयोग पर
 - स्थानीय विवेक को समाप्त करने पर
36. नीचे-से-ऊपर दृष्टिकोण की प्रमुख आलोचना क्या है ?
- यह केंद्रीय योजना की अनदेखी करता है और असंगतता पैदा कर सकता है
 - यह बहुत अधिक एकरूपता लाता है
 - यह स्थानीय आवश्यकताओं को नकारता है
 - यह केवल न्यायालयों पर निर्भर करता है
37. सड़क-स्तरीय नौकरशाही मुख्यतः किन्हें कहा जाता है ?
- सांसदों को
 - स्थानीय अधिकारी जैसे शिक्षक, पुलिसकर्मी, कल्याण अधिकारी
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
 - मंत्रिमंडल के मंत्रियों को
38. लिप्स्की के अनुसार सड़क-स्तरीय नौकरशाह किस रूप में कार्य करते हैं ?
- केवल नियमों का पालन करने वाले
 - व्यवहार में नीति-निर्माता
 - सिर्फ आदेशों के प्रशासक
 - निष्पक्ष रिकॉर्ड रखने वाले

39. Why are street-level bureaucrats often criticized?
- (A) They completely ignore rules
(B) They create inequalities in service delivery due to personal discretion
(C) They frame policies themselves
(D) They never interact with citizens
40. Which of the following is a major challenge in policy implementation?
- (A) Adequate financial resources
(B) Lack of coordination among implementing agencies
(C) Public participation in decision-making
(D) Strong political support
41. One key condition for effective implementation is:
- (A) Political and administrative commitment
(B) Absence of accountability
(C) Total discretion without monitoring
(D) Central policies with no local adaptation
42. Which factor often leads to implementation failure?
- (A) Stakeholder cooperation
(B) Inadequate resources and manpower
(C) Proper communication channels
(D) Training of staff
39. सड़क-स्तरीय नौकरशाहों की आलोचना क्यों होती है ?
- (A) वे पूरी तरह नियमों की अनदेखी करते हैं
(B) वे व्यक्तिगत विवेक के कारण सेवाओं में असमानता पैदा करते हैं
(C) वे खुद नीतियाँ बनाते हैं
(D) वे कभी नागरिकों से संपर्क नहीं करते
40. नीति-कार्यान्वयन में एक प्रमुख चुनौती कौन-सी है ?
- (A) पर्याप्त वित्तीय संसाधन
(B) कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी
(C) निर्णय-निर्माण में जनसहभागिता
(D) मजबूत राजनीतिक समर्थन
41. प्रभावी कार्यान्वयन की एक प्रमुख शर्त है :
- (A) राजनीतिक और प्रशासनिक प्रतिबद्धता
(B) जवाबदेही का अभाव
(C) बिना निगरानी के पूर्ण विवेकाधिकार
(D) स्थानीय अनुकूलन के बिना केंद्रीय नीतियाँ
42. कार्यान्वयन विफलता का कारण अक्सर क्या होता है ?
- (A) हितधारकों का सहयोग
(B) अपर्याप्त संसाधन और जनशक्ति
(C) उचित संचार चैनल
(D) कर्मचारियों का प्रशिक्षण

43. A major challenge in developing countries is:
- (A) Excessive citizen awareness
(B) Bureaucratic delays and corruption
(C) Over-abundance of trained staff
(D) Very strong local governments
44. Which of the following is NOT a condition for successful policy implementation?
- (A) Adequate resources
(B) Supportive institutional framework
(C) Strong monitoring system
(D) Total secrecy and lack of transparency
45. Which institution is primarily responsible for overall policy implementation in India?
- (A) Judiciary
(B) Executive (Government machinery)
(C) Election Commission
(D) Media
46. Which body plays a supportive role in policy implementation by providing judicial review?
- (A) Executive
(B) Legislature
(C) Judiciary
(D) Political parties
43. विकासशील देशों में एक प्रमुख चुनौती है :
- (A) अत्यधिक नागरिक जागरूकता
(B) नौकरशाही की देरी और भ्रष्टाचार
(C) प्रशिक्षित कर्मचारियों की अधिकता
(D) बहुत मजबूत स्थानीय सरकारें
44. निम्नलिखित में से कौन सफल नीति-कार्यान्वयन की शर्त नहीं है ?
- (A) पर्याप्त संसाधन
(B) सहायक संस्थागत ढांचा
(C) मजबूत निगरानी प्रणाली
(D) पूर्ण गोपनीयता और पारदर्शिता का अभाव
45. भारत में समग्र नीति-कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी किस संस्था की है ?
- (A) न्यायपालिका
(B) कार्यपालिका (सरकारी तंत्र)
(C) चुनाव आयोग
(D) मीडिया
46. कौन-सा निकाय न्यायिक पुनरावलोकन प्रदान कर कार्यान्वयन में सहायक भूमिका निभाता है?
- (A) कार्यपालिका
(B) विधायिका
(C) न्यायपालिका
(D) राजनीतिक दल

47. NGOs and Civil Society organizations contribute to implementation by:
- Drafting the Constitution
 - Delivering services, creating awareness, and monitoring outcomes
 - Passing laws in Parliament
 - Conducting elections
48. In India, NITI Aayog supports policy implementation mainly through:
- Judicial activism
 - Cooperative federalism and policy guidance
 - Direct law enforcement
 - Election management
49. Public Accounts Committee (PAC) in Parliament ensures:
- Efficient financial use and accountability in implementation
 - Drafting of new laws
 - Appointment of judges
 - International treaty ratification
50. Successful policy implementation requires coordination among:
- Legislature, Executive, Judiciary, Bureaucracy, and Civil Society
 - Only Parliament and Executive
 - Only Judiciary and Media
 - Only political parties
47. एनजीओ और सिविल सोसाइटी संगठन कार्यान्वयन में कैसे योगदान करते हैं ?
- संविधान का मसौदा तैयार कर
 - सेवाएँ प्रदान कर, जागरूकता पैदा कर और परिणामों की निगरानी कर
 - संसद में कानून पारित कर
 - चुनाव कराकर
48. भारत में नीति आयोग नीति-कार्यान्वयन का समर्थन मुख्यतः किस प्रकार करता है ?
- न्यायिक सक्रियता द्वारा
 - सहकारी संघवाद और नीति मार्गदर्शन द्वारा
 - प्रत्यक्ष कानून प्रवर्तन द्वारा
 - चुनाव प्रबंधन द्वारा
49. संसद की लोक लेखा समिति (PAC) सुनिश्चित करती है :
- कार्यान्वयन में कुशल वित्तीय उपयोग और जवाबदेही
 - नए कानूनों का मसौदा
 - न्यायाधीशों की नियुक्ति
 - अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि
50. सफल नीति-कार्यान्वयन के लिए किसके बीच समन्वय आवश्यक है ?
- विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, नौकरशाही और सिविल सोसाइटी
 - केवल संसद और कार्यपालिका
 - केवल न्यायपालिका और मीडिया
 - केवल राजनीतिक दल

- | | |
|---|--|
| 51. Ayushman Bharat scheme was launched in which year? | 51. आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी ? |
| (A) 2014 | (A) 2014 |
| (B) 2016 | (B) 2016 |
| (C) 2018 | (C) 2018 |
| (D) 2020 | (D) 2020 |
| 52. The Ayushman Bharat scheme primarily aims to provide: | 52. आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है ? |
| (A) Employment to rural poor | (A) ग्रामीण गरीबों को रोजगार देना |
| (B) Universal health coverage | (B) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज उपलब्ध कराना |
| (C) Digital literacy | (C) डिजिटल साक्षरता बढ़ाना |
| (D) Housing for all | (D) सभी को आवास प्रदान करना |
| 53. The Digital India campaign was officially launched in: | 53. डिजिटल इंडिया अभियान आधिकारिक रूप से किस वर्ष शुरू किया गया था? |
| (A) 2014 | (A) 2014 |
| (B) 2015 | (B) 2015 |
| (C) 2016 | (C) 2016 |
| (D) 2017 | (D) 2017 |
| 54. The main objective of Digital India is: | 54. डिजिटल इंडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? |
| (A) To provide direct employment | (A) प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करना |
| (B) To transform India into a digitally empowered society and knowledge economy | (B) भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना |
| (C) To promote only e-commerce | (C) केवल ई-कॉमर्स को बढ़ावा देना |
| (D) To provide free electricity | (D) मुफ्त बिजली देना |
| 55. Which of the following is NOT a pillar of Digital India? | 55. निम्नलिखित में से कौन-सा डिजिटल इंडिया का स्तंभ नहीं है? |
| (A) Digital Infrastructure | (A) डिजिटल अवसंरचना |
| (B) Governance and Services on Demand | (B) माँग शासन और सेवाएँ |
| (C) Digital Literacy | (C) डिजिटल साक्षरता |
| (D) Food Security | (D) खाद्य सुरक्षा |

- | | |
|---|---|
| <p>56. In which year was the MGNREGA Act passed?</p> <p>(A) 2005</p> <p>(B) 2007</p> <p>(C) 2010</p> <p>(D) 2012</p> | <p>56. मनरेगा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था?</p> <p>(A) 2005</p> <p>(B) 2007</p> <p>(C) 2010</p> <p>(D) 2012</p> |
| <p>57. Which ministry is responsible for the implementation of MGNREGA?</p> <p>(A) Ministry of Rural Development</p> <p>(B) Ministry of Health and Family Welfare</p> <p>(C) Ministry of Labour and Employment</p> <p>(D) Ministry of Finance</p> | <p>57. मनरेगा के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की है?</p> <p>(A) ग्रामीण विकास मंत्रालय</p> <p>(B) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय</p> <p>(C) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय</p> <p>(D) वित्त मंत्रालय</p> |
| <p>58. Which of the following is a typical transnational actor?</p> <p>(A) World Bank</p> <p>(B) Local Panchayat</p> <p>(C) State Assembly</p> <p>(D) District Court</p> | <p>58. निम्नलिखित में से एक सामान्य ट्रांसनेशनल अभिनेता कौन है?</p> <p>(A) वर्ल्ड बैंक</p> <p>(B) स्थानीय पंचायत</p> <p>(C) राज्य विधानसभा</p> <p>(D) जिला न्यायालय</p> |
| <p>59. The role of transnational actors in policy-making is mainly to:</p> <p>(A) Directly enforce laws within a country</p> <p>(B) Provide funding, technical assistance, and policy guidance</p> <p>(C) Conduct national elections</p> <p>(D) Draft local municipal regulations</p> | <p>59. नीति निर्माण में ट्रांसनेशनल एक्टर्स की मुख्य भूमिका क्या है?</p> <p>(A) सीधे देश में कानून लागू करना</p> <p>(B) वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और नीति मार्गदर्शन प्रदान करना</p> <p>(C) राष्ट्रीय चुनाव कराना</p> <p>(D) स्थानीय नगरपालिका नियम बनाना</p> |

60. United Nations agencies influence national policy by:
- Passing domestic laws
 - Offering international guidelines and best practices
 - Conducting judicial review
 - Running local schools
61. Transnational corporations (TNCs) can influence public policy by:
- Ignoring regulatory frameworks
 - Lobbying governments and shaping economic policies
 - Drafting constitutions
 - Conducting criminal investigations
62. IMF and World Bank influence policy in developing countries primarily through:
- Military intervention
 - Conditional financial assistance and structural adjustment programs
 - Conducting elections
 - Judicial rulings
63. Which of the following is a positive impact of globalization on policy-making?
- Reduced foreign investment
 - Adoption of international best practices and standards
 - Restriction on information flow
 - Limitation on technology transfer
60. संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ राष्ट्रीय नीति को कैसे प्रभावित करती हैं?
- घरेलू कानून पास करके
 - अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देश और सर्वोत्तम प्रथाएँ प्रदान करके
 - न्यायिक समीक्षा करके
 - स्थानीय स्कूल चलाकर
61. ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन (TNCs) सार्वजनिक नीति को कैसे प्रभावित कर सकती हैं?
- नियामक ढांचे की अनदेखी करके
 - सरकारों पर लॉबी करके और आर्थिक नीतियों को आकार देकर
 - संविधान का मसौदा तैयार करके
 - आपराधिक जांच करके
62. आई.एम.एफ. और वर्ल्ड बैंक विकासशील देशों में नीति को मुख्य रूप से कैसे प्रभावित करते हैं?
- सैन्य हस्तक्षेप द्वारा
 - शर्तीय वित्तीय सहायता और संरचनात्मक सुधार कार्यक्रमों के माध्यम से
 - चुनाव कराकर
 - न्यायिक निर्णय देकर
63. नीति निर्माण पर वैश्वीकरण का सकारात्मक प्रभाव कौन-सा है?
- विदेशी निवेश में कमी
 - अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों को अपनाना
 - सूचना प्रवाह पर प्रतिबंध
 - तकनीक हस्तांतरण सीमा

64. Globalization promotes policy reforms in developing countries by:
- Reducing competition
 - Encouraging modernization and efficiency
 - Isolating local markets
 - Limiting technology adoption
65. A negative impact of globalization on policy-making can be:
- Exposure to international best practices
 - Policy dependence on foreign financial institutions
 - Technology transfer
 - Improved governance transparency
66. Foreign direct investment (FDI) influences domestic policy because:
- It limits international cooperation
 - Governments adjust policies to attract and regulate investment
 - It removes national budget control
 - It eliminates local governance
67. Which part of the Indian Constitution lays down the Directive Principles of State Policy (DPSP)?
- Part-III
 - Part-IV
 - Part-V
 - Part-VI
64. वैश्वीकरण विकासशील देशों में नीति सुधार को कैसे बढ़ावा देता है?
- प्रतिस्पर्धा कम करके
 - आधुनिकीकरण और दक्षता को प्रोत्साहित करके
 - स्थानीय बाजारों को अलग करके
 - तकनीक अपनाने को सीमित करके
65. नीति निर्माण में वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है?
- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का सामना
 - विदेशी वित्तीय संस्थाओं पर नीति निर्भरता
 - तकनीक हस्तांतरण
 - शासन में पारदर्शिता में सुधार
66. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) घरेलू नीति को प्रभावित करता है क्योंकि :
- यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सीमित करता है
 - सरकारें निवेश को आकर्षित और नियंत्रित करने के लिए नीतियाँ समायोजित करती हैं
 - यह राष्ट्रीय बजट नियंत्रण हटा देता है
 - यह स्थानीय शासन समाप्त कर देता है
67. भारतीय संविधान का कौन-सा भाग राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत (DPSP) को निर्धारित करता है?
- भाग-III
 - भाग-IV
 - भाग-V
 - भाग-VI

68. The Directive Principles of State Policy are:
 (A) Justiciable
 (B) Non-justiciable
 (C) Optional for Parliament
 (D) Judicially enforceable
69. Which article obliges the State to provide free and compulsory education for children?
 (A) Article 45
 (B) Article 21A
 (C) Article 39A
 (D) Article 51A
70. Which article requires the State to raise the level of nutrition and standard of living?
 (A) Article 38
 (B) Article 39
 (C) Article 41
 (D) Article 43
71. Under the Constitution, which institution is responsible for national economic planning?
 (A) RBI
 (B) NITI Aayog
 (C) Finance Commission
 (D) UPSC
72. Which article provides for protection of the environment and forests?
 (A) Article 48A
 (B) Article 39
 (C) Article 41
 (D) Article 21
68. राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांत हैं :
 (A) न्यायसंगत
 (B) गैर-न्यासंगत
 (C) संसद के लिए वैकल्पिक
 (D) न्यायिक रूप से प्रवर्तनीय
69. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए बाध्य करता है?
 (A) अनुच्छेद 45
 (B) अनुच्छेद 21A
 (C) अनुच्छेद 39A
 (D) अनुच्छेद 51A
70. कौन-सा अनुच्छेद राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर बढ़ाने के लिए बाध्य करता है?
 (A) अनुच्छेद 38
 (B) अनुच्छेद 39
 (C) अनुच्छेद 41
 (D) अनुच्छेद 43
71. संविधान के तहत राष्ट्रीय आर्थिक योजना के लिए कौन-सी संस्था जिम्मेदार है?
 (A) आर.बी.आई.
 (B) नीति आयोग
 (C) वित्त आयोग
 (D) यू.पी.एस.सी.
72. पर्यावरण और वन संरक्षण की सुरक्षा कौन-सा अनुच्छेद प्रदान करता है?
 (A) अनुच्छेद 48A
 (B) अनुच्छेद 39
 (C) अनुच्छेद 41
 (D) अनुच्छेद 21

73. Parliament plays a key role in policy-making by:
- Drafting and passing legislation
 - Enforcing laws directly
 - Conducting judicial review
 - Running state governments
74. Which of the following committees of Parliament is primarily involved in examining financial bills?
- Public Accounts Committee
 - Estimates Committee
 - Committee on Government Assurances
 - Committee on Privileges
75. Which article gives Parliament the power to make laws on subjects in the Union List?
- Article 245
 - Article 256
 - Article 312
 - Article 352
76. Money bills can only be introduced in:
- Rajya Sabha
 - Lok Sabha
 - Both Houses simultaneously
 - NITI Aayog
77. Which parliamentary instrument allows MPs to suggest improvements in government schemes?
- Ordinances
 - Questions, motions, and resolutions
 - Executive orders
 - Presidential notifications
73. संसद नीति निर्माण में मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाती है?
- कानून का मसौदा तैयार करना और पारित करना
 - सीधे कानून लागू करना
 - न्यायिक समीक्षा करना
 - राज्य सरकारें चलाना
74. संसद की निम्नलिखित समितियों में से कौन वित्तीय विधेयकों की जांच में मुख्य रूप से शामिल है?
- लोक लेखा समिति
 - अनुमान समिति
 - सरकारी आश्वासनों पर समिति
 - विशेषाधिकार समिति
75. कौन-सा अनुच्छेद संसद को संघ सूची में विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है?
- अनुच्छेद 245
 - अनुच्छेद 256
 - अनुच्छेद 312
 - अनुच्छेद 352
76. वित्त विधेयक केवल किसमें प्रस्तुत किया जा सकता है?
- राज्यसभा
 - लोकसभा
 - दोनों में एक साथ
 - नीति आयोग
77. कौन-सा संसदीय साधन सांसदों को सरकारी योजनाओं में सुधार का सुझाव देने की अनुमति देता है?
- अध्यादेश
 - प्रश्न, प्रस्ताव और संकल्प
 - कार्यकारी आदेश
 - राष्ट्रपति नोटिफिकेशन

78. Committees like the Committee on Petitions contribute to policy-making by :
- Drafting bills
 - Examining citizens' grievances and suggesting reforms
 - Conducting elections
 - Issuing executive orders
79. Civil society organizations influence policy-making by:
- Drafting laws independently
 - Advocating for social issues and representing public interests
 - Conducting elections
 - Enforcing laws directly
80. Pressure groups differ from political parties in that they:
- Contest elections to form government
 - Seek to influence policy without directly holding power
 - Write constitutions
 - Conduct judicial reviews
81. Which of the following is an example of a pressure group in India?
- Indian Medical Association
 - Lok Sabha
 - Election Commission
 - RBI
78. याचिका समिति जैसी समितियाँ नीति निर्माण में कैसे योगदान देती हैं?
- विधेयक का मसौदा तैयार करके
 - नागरिकों की शिकायतों की जांच और सुधार सुझाकर
 - चुनाव कराकर
 - कार्यकारी आदेश जारी करके
79. नागरिक समाज संगठन नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करते हैं?
- स्वतंत्र रूप से कानून का मसौदा तैयार करके
 - सामाजिक मुद्दों की वकालत करके और जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करके
 - चुनाव कराकर
 - सीधे कानून लागू करके
80. दबाव समूह राजनीतिक दलों से किस प्रकार भिन्न होते हैं?
- सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ते हैं
 - सीधे सत्ता में रहकर नहीं बल्कि नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं
 - संविधान का मसौदा तैयार करते हैं
 - न्यायिक समीक्षा करते हैं
81. भारत में निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह का उदाहरण है?
- भारतीय चिकित्सा संघ
 - लोकसभा
 - चुनाव आयोग
 - आर.बी.आई.

- | | |
|---|---|
| <p>82. Environmental NGOs influence policy by:</p> <p>(A) Conducting elections</p> <p>(B) Advocating for sustainable development and environmental protection</p> <p>(C) Issuing ordinances</p> <p>(D) Drafting national budgets</p> | <p>82. पर्यावरण एन.जी.ओ. नीति को कैसे प्रभावित करते हैं?</p> <p>(A) चुनाव कराकर</p> <p>(B) सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की वकालत करके</p> <p>(C) अध्यादेश जारी करके</p> <p>(D) राष्ट्रीय बजट तैयार करके</p> |
| <p>83. Trade unions act as pressure groups by:</p> <p>(A) Controlling political parties</p> <p>(B) Representing workers' interests in labor policy and reforms</p> <p>(C) Implementing government schemes</p> <p>(D) Drafting civil codes</p> | <p>83. ट्रेड यूनियन दबाव समूह के रूप में कैसे कार्य करते हैं?</p> <p>(A) राजनीतिक दलों को नियंत्रित करके</p> <p>(B) श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करके श्रम नीति और सुधार में</p> <p>(C) सरकारी योजनाओं को लागू करके</p> <p>(D) नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करके</p> |
| <p>84. A limitation of civil society in policy-making is:</p> <p>(A) It always has unlimited resources</p> <p>(B) Its influence may be unequal and fragmented</p> <p>(C) It can enforce laws directly</p> <p>(D) It can dissolve Parliament</p> | <p>84. नीति निर्माण में नागरिक समाज की एक सीमा क्या है?</p> <p>(A) इसके पास हमेशा असीमित संसाधन होते हैं</p> <p>(B) इसका प्रभाव असमान और विखंडित हो सकता है</p> <p>(C) यह सीधे कानून लागू कर सकता है</p> <p>(D) यह संसद भंग कर सकता है</p> |
| <p>85. The judiciary ensures that policies adhere to:</p> <p>(A) Political party preferences</p> <p>(B) Constitutional provisions and fundamental rights</p> <p>(C) Only executive orders</p> <p>(D) Election manifestos</p> | <p>85. न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि नीतियाँ किसके अनुरूप हों?</p> <p>(A) राजनीतिक दल की प्राथमिकताओं</p> <p>(B) संवैधानिक प्रावधानों और मौलिक अधिकारों</p> <p>(C) केवल कार्यकारी आदेश</p> <p>(D) चुनावी घोषणा-पत्र</p> |

86. Public Interest Litigation (PIL) allows judiciary to influence policy by:
- Directly passing laws
 - Addressing issues of public importance brought by citizens
 - Controlling budgets
 - Conducting elections
87. The High Courts influence policy making through:
- Writ jurisdiction under Article 226
 - Drafting parliamentary bills
 - Conducting state elections
 - Approving budgets
88. Courts can guide policy-making indirectly by:
- Issuing advisory opinions and interpretation that shape government actions
 - Dissolving Parliament
 - Controlling political parties
 - Conducting census
89. Which policy aims to provide universal school education for children aged 6–14 in India?
- National Education Policy-2020
 - Mid-Day Meal Scheme
 - Right to Education Act
 - Sarva Shiksha Abhiyan
86. जनहित याचिका (PIL) न्यायपालिका को नीति को प्रभावित करने की अनुमति देती है:
- सीधे कानून पास करके
 - नागरिकों द्वारा लाए गए सार्वजनिक महत्व के मुद्दों को संबोधित करके
 - बजट नियंत्रित करके
 - चुनाव कराकर
87. उच्च न्यायालय नीति निर्माण को कैसे प्रभावित करता है?
- अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार
 - संसदीय बिल तैयार करके
 - राज्य चुनाव कराकर
 - बजट अनुमोदन करके
88. न्यायालय अप्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण को कैसे मार्गदर्शित कर सकते हैं?
- परामर्शात्मक राय और व्याख्या जारी करके जो सरकारी कार्रवाइयों को आकार देती है
 - संसद भंग करके
 - राजनीतिक दलों को नियंत्रित करके
 - जनगणना कराकर
89. भारत में 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए सार्वभौमिक विद्यालय शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य किस नीति का है?
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
 - मध्याह्न भोजन योजना
 - शिक्षा का अधिकार अधिनियम
 - सर्व शिक्षा अभियान

90. Which scheme provides financial support to farmers during crop failure?
- (A) Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
(B) PM-Kisan Samman Nidhi
(C) National Food Security Act
(D) Rashtriya Krishi Vikas Yojana
91. Beti Bachao, Beti Padhao campaign focuses on:
- (A) Women's safety and education
(B) Rural sanitation
(C) Food security
(D) Digital literacy
92. Which policy aims to improve the quality of higher education in India?
- (A) National Education Policy-2020
(B) Mid-Day Meal Scheme
(C) Sarva Shiksha Abhiyan
(D) Skill India Mission
93. The National Health Mission focuses on:
- (A) Urban development
(B) Primary health care and maternal-child health
(C) Digital infrastructure
(D) Renewable energy
90. कौन-सी योजना फसल नष्ट होने पर किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- (A) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
(B) राष्ट्रीय किसान सम्मान निधि
(C) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
(D) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
91. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान किस पर केंद्रित है?
- (A) महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा
(B) ग्रामीण स्वच्छता
(C) खाद्य सुरक्षा
(D) डिजिटल साक्षरता
92. किस नीति का उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना है?
- (A) राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020
(B) मध्याह्न भोजन योजना
(C) सर्व शिक्षा अभियान
(D) स्किल इंडिया मिशन
93. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पर केंद्रित है?
- (A) शहरी विकास
(B) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और मातृ-शिशु स्वास्थ्य
(C) डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
(D) नवीकरणीय ऊर्जा

94. PM-Kisan Samman Nidhi provides:
- Crop insurance
 - Direct income support to farmers
 - Health insurance
 - Free school meals
95. Pradhan Mantri Awas Yojana aims to:
- Provide affordable housing for all
 - Subsidize fertilizers
 - Promote renewable energy
 - Improve school education
96. National Food Security Act (NFSA) ensures:
- Free healthcare
 - Subsidized food grains to eligible households
 - Financial literacy
 - Housing support
97. PM-SVANidhi scheme supports:
- Street vendors with micro-credit loans
 - Farmers with subsidies
 - Students with scholarships
 - Health workers with incentives
94. पीएम-किसान सम्मान निधि क्या प्रदान करती है?
- फसल बीमा
 - किसानों को सीधे आय सहायता
 - स्वास्थ्य बीमा
 - मुफ्त विद्यालय भोजन
95. प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है:
- सभी के लिए किफायती आवास प्रदान करना
 - उर्वरक पर सब्सिडी देना
 - नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना
 - स्कूल शिक्षा में सुधार
96. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) सुनिश्चित करता है:
- मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल
 - पात्र परिवारों को सब्सिडी वाला अन्न
 - वित्तीय साक्षरता
 - आवास सहायता
97. पीएम-स्वनिधि योजना किसका समर्थन करती है?
- स्ट्रीट वेंडरों को सूक्ष्म ऋण
 - किसानों को सब्सिडी
 - छात्रों को छात्रवृत्ति
 - स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन

- | | |
|---|---|
| <p>98. Swachh Bharat Mission primarily focuses on:</p> <p>(A) Rural and urban sanitation</p> <p>(B) Women's education</p> <p>(C) Crop insurance</p> <p>(D) Digital literacy</p> | <p>98. स्वच्छ भारत मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?</p> <p>(A) ग्रामीण और शहरी स्वच्छता</p> <p>(B) महिला शिक्षा</p> <p>(C) फसल बीमा</p> <p>(D) डिजिटल साक्षरता</p> |
| <p>99. Which of the following is a flagship e-governance program of India aimed at providing digital services to citizens?</p> <p>(A) Digital India</p> <p>(B) Make in India</p> <p>(C) Skill India</p> <p>(D) Swachh Bharat Mission</p> | <p>99. भारत की कौन-सी प्रमुख ई-गवर्नेंस योजना नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए है?</p> <p>(A) डिजिटल इंडिया</p> <p>(B) मेक इन इंडिया</p> <p>(C) स्किल इंडिया</p> <p>(D) स्वच्छ भारत मिशन</p> |
| <p>100. The e-governance initiative 'DigiLocker' primarily focuses on:</p> <p>(A) Storing and accessing documents digitally</p> <p>(B) Providing online education</p> <p>(C) Monitoring health records only</p> <p>(D) Tax collection</p> | <p>100. ई-गवर्नेंस पहल 'DigiLocker' मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?</p> <p>(A) दस्तावेजों को डिजिटल रूप से स्टोर और एक्सेस करना</p> <p>(B) ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना</p> <p>(C) केवल स्वास्थ्य रिकॉर्ड की निगरानी</p> <p>(D) कर संग्रह</p> |

Rough Work / रफ कार्य

Example :

Question :

Q.1 (A) ● (C) (D)

Q.2 (A) (B) ● (D)

Q.3 (A) ● (C) (D)

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer Sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination, candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager & cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ● (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ● (D)

प्रश्न 3 (A) ● (C) (D)

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ०एम०आर० उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैल्कुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण: प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्नपुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरिज की दूसरी प्रश्नपुस्तिका प्राप्त कर लें।